



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491]
No. 491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अग्रहायण 21, 1919
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 700(अ).—रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) नियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 के खण्ड (क) उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और सेवा शर्तों) नियम, 1987 में निम्न प्रकार से संशोधित करती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों) संशोधन नियम, 1997 कहा जाएगा।

2. ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तों) नियम, 1987 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) यदि अध्यक्ष महोदय सामान्य आवास पूल के सरकारी आवास का लाभ नहीं लेते तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर से मकान किराया भत्ता लेने के हकदार होंगे।

(4) यदि कोई सदस्य सामान्य आवास पूल से सरकारी आवास का लाभ नहीं लेता तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर मकान किराया भत्ता लेने का हकदार होगा।

(5) जो अध्यक्ष सरकारी आवास का प्रयोग करते हैं, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर किरायामुक्त सुसज्जित आवास (विद्युत उपकरणों सहित) का प्रयोग करने के हकदार होंगे। वे आवासीय प्रयोग के दौरान जल व विद्युत की खपत की 12 हजार रुपए तक की वार्षिक राशि की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

(6) जो सदस्य सरकारी आवास का प्रयोग करते हैं, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर किरायामुक्त सुसज्जित आवास (विद्युत उपकरणों सहित) का प्रयोग करने के हकदार होंगे। वे आवासीय प्रयोग के दौरान जल व विद्युत की खपत की 12 हजार रुपए तक की वार्षिक राशि की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में “150 लिटर पेट्रोल प्रति माह” शब्दों के स्थान पर “200 लिटर ईंधन प्रति माह” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 7/11/96-बी.ओ. I(i)]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियम दिनांक 12 जनवरी, 1987 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 26(अ) के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G. S. R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (1 of 1986), the Central Government hereby amends the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members), Rules, 1987 as follows namely :—

1. These rules may be called the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Amendment Rules, 1997.

2. These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In rule 10, of the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members), Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules) after sub rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

(3) If the Chairman does not avail himself of the official residence from the general pool accommodation, he shall be entitled to house rent at the rate admissible to a judge of the High Court.

(4) If the Member does not avail himself of the official residence from the general pool accommodation, he shall be entitled to house rent at the rate admissible to a judge of the High Court.

(5) The Chairman who avails himself of the use of an official residence shall be entitled to use of a furnished residence (including electrical appliances) free of rent at his residence at the rate admissible to a judge of a high Court. He shall also be entitled to re-imbursement of charges on account of water and electricity consumed at his residence not exceeding rupees twelve thousand per annum.

(6) A Member who avails himself of the use of an official residence shall be entitled to use of a furnished residence (including electrical appliances) free of rent at his residence at the rate admissible to a judge of a High Court. He shall also be entitled to re-imbursement of charges on account of water and electricity consumed at his residence not exceeding rupees twelve thousand per annum."

4. In rule 11 of the said rules for the words "one hundred and fifty litres of petrol per month" the words "two hundred litres of fuel per month" shall be substituted.

[F. No. 7/11/96 BO.I(i)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

Note:— The Principal rules were published vide Notification No. G. S. R. 26(E) dated 12th January, 1987.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 701(अ).—रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) नियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 के खण्ड (क) उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 1987 में निम्न प्रकार से संशोधित करती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 1997 कहा जाएगा ।

2. ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियम, 1987 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) यदि अध्यक्ष महोदय सामान्य आवास पूल के सरकारी आवास का लाभ नहीं लेते तो वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर से मकान किराया भत्ता लेने के हकदार होंगे ।

(4) यदि कोई सदस्य सामान्य आवास पूल से सरकारी आवास का लाभ नहीं लेता तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर मकान किराया भत्ता लेने का हकदार होगा ।

(5) जो अध्यक्ष सरकारी आवास का प्रयोग करते हैं, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर किरायामुक्त सुसज्जित आवास (विद्युत उपकरणों सहित) का प्रयोग करने के हकदार होंगे । वे आवासीय प्रयोग के दौरान जल व विद्युत की खपत की 12 हजार रुपए तक की वार्षिक राशि की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे ।

(6) जो सदस्य सरकारी आवास का प्रयोग करते हैं, वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय दर पर किरायामुक्त सुसज्जित आवास (विद्युत उपकरणों सहित) का प्रयोग करने के हकदार होंगे। वे आवासीय प्रयोग के दौरान जल व विद्युत की खपत की 12 हजार रुपए तक की वार्षिक राशि की प्रतिपूर्ति के भी हकदार होंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 11 में "150 लिटर पेट्रोल प्रति माह" शब्दों के स्थान पर "200 लिटर ईंधन प्रति माह" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 7/11/96-बी.ओ. I(ii)]

एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख नियम दिनांक 10 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 381 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और तदोपरान्त निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :—

क्र. सं.	का. आ. सं.	तारीख
1.	सा. का. नि. 669(अ)	28-06-1989

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G. S. R. 701(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, (1 of 1986), the Central Government hereby amends the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members), Rules, 1987 as follows :—

1. These rules may be called the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members) Amendment Rules, 1997.

2. These rules shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In rule 10, of the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Other Members), Rules, 1987 (hereinafter referred to as the said rules) after sub-rule 2 the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3) If the Chairman does not avail himself of the official residence from the general pool accommodation, he shall be entitled to house rent at the rate admissible to a judge of the Supreme Court.

(4) If the Member does not avail himself of the official residence from the general pool accommodation, he shall be entitled to house rent at the rate admissible to a judge of the High Court.

(5) The Chairman who avails himself of an official residence shall be entitled to furnished residence (including electrical appliances) free of rent at his residence at the rate admissible to a judge of the Supreme Court. He shall also be entitled to re-imbursement of charges on account of water and electricity consumed at his residence not exceeding rupees twelve thousand per annum.

(6) A Member who avails himself of an official residence shall be entitled to furnished residence (including electrical appliances) free of rent at his residence at the rate admissible to a judge of a High Court. He shall also be entitled to re-imbursement of charges on account of water and electricity consumed at his residence not exceeding rupees twelve thousand per annum."

4. In rule 11 of the said rules for the words "one hundred and fifty litres of petrol per month" the words "two hundred litres of fuel per month" shall be substituted.

[F. No. 7/11/96-BO.I(ii)]

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

Note :—The Principal Rule was published vide Notification No. G. S. R. 381(E) dated 10th April, 1987 and subsequently amended vide the following notifications :—

Sr. No.	S.O. No.	Date
1.	G.S.R. 669(E)	28-06-1989

